सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया भाजपा ने

यह फैसला राजस्थान की दो प्रभावशाली जातियों जाट और गुर्जर वर्ग को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने राजस्थान के दो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। पार्टी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। यह फैसला केवल राज्यसभा सीटों तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे प्रदेश की दो प्रभावशाली जातियों जाट और गुर्जर समाज को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। गुरूवार देर शाम डॉ. सतीश पूनिया एवं डॉ. अलका गुर्जर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाए जाने पर मिठाई खिलाकर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं का व्यापक संगठनात्मक अनुभव, जनसेवा के प्रति समर्पण और राष्ट्रिहत के प्रति प्रतिबद्धता संसद में राजस्थान एवं देश की आकांक्षाओं को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करेगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल उपस्थित रहे।

ज्ञात रहे कि सतीश पूनिया वर्तमान में हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि अलका गुर्जर लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा रही हैं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद अलका गुर्जर ने बताया कि वे पार्टी की वर्चुअल बैठक में शामिल थीं, तभी केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का फोन आया और उन्हें टिकट मिलने की जानकारी दी गई।

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रहे सतीश पूनिया लंबे समय से संगठन के महत्वपूर्ण चेहरों में शामिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें पहले बिहार तथा बाद में हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी। अब राज्यसभा भेजने का निर्णय संगठन में उनकी भूमिका और नेतृत्व पर केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे का संकेत माना जा रहा है।

अलका गुर्जर भी भाजपा की जमीनी राजनीति से जुड़ा बड़ा चेहरा हैं। वे एक बार विधायक रह चुकी हैं और गुर्जर समाज में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके पति डॉ. नाथू सिंह गुर्जर भी भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं तथा संगठन में कई अहम पदों पर कार्य कर चुके हैं। राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है, जिसके चलते ये सीटें रिक्त हो रही हैं।

विधानसभा के मौजूदा संख्या बल के अनुसार एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 51 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है। भाजपा के पास दो सीटें जीतने लायक संख्या तो है, लेकिन तीसरी सीट के लिए उसे करीब 35 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी। राजनीतिक समीकरणों के अनुसार यदि भाजपा को आरएलडी, निर्दलीय, बसपा और बीटीपी के सभी संभावित वोट भी मिल जाएं, तब भी तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए लगभग 20 वोट कम पडेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने फिलहाल दो उम्मीदवार उतारकर सुरक्षित रणनीति अपनाई है। हालांकि तीसरी सीट को लेकर अंतिम समय तक राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। यदि भाजपा तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो यह चुनाव केवल संख्या बल का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रबंधन और रणनीतिक कौशल की परीक्षा बन सकता है।

फिलहाल सतीश पूनिया और अलका गुर्जर की उम्मीदवारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा आगामी चुनावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित होने के बाद डॉ. सतीश पूनिया एवं डॉ. अलका गुर्जर ने गुरूवार देर शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट की।

- **ज्ञात रहे कि सतीश पूनियां वर्तमान में हरियाणा प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जबकि अलका गुर्जर लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभा रही है।**

पीएम सूर्यघर योजना में श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए राजस्थान को 6 पुरस्कार

केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने डिस्कॉम्स चेयरमैन को चार अलग-अलग श्रेणियों में प्रदान किए अवॉर्ड

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरूवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा को चार अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए।

जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को सम्मानित किया है। केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने गुरूवार को दिल्ली में आयोजित समारोह में यह सम्मान प्रदान किए। ऊर्जा सचिव एवं राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन आरती डोगरा ने चार अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार ग्रहण किए।

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने योजना के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया। इस दौरान 90 लाख से 1.50 करोड़ विद्युत उपभोक्ता वाले राज्यों के अंतर्गत मई माह के दौरान रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के सर्वाधिक आवेदन, इंस्टॉलेशन, निरीक्षण तथा वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की कैटिगरी में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इसी तरह सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले 10 सर्वश्रेष्ठ जिलों की कैटेगरी में जयपुर को 7वें स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। जयपुर डिस्कॉम की अधीक्षण अभियंता (पीएम सूर्यघर) महिमा साराभाई ने यह सम्मान ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त वेंडर श्रेणी में मई माह के दौरान उत्तर क्षेत्र के राज्यों में सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन की कैटिगरी में मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को भी द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार राजस्थान को इस योजना में कुल 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष मई माह के दौरान इस योजना के अन्तर्गत जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर वितरण निगमों में 39279 आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 27700 आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया गया, 26632 रूफ टॉप सोलर इंस्टॉल हुए और 177 नए वेंडरों को योजना से जोड़ा गया।

बिना सूचना बाल कल्याण समिति में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर मांगा जवाब

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर की जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पद पर बिना आम सूचना निकाले नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने पर बाल अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, कमिश्नर व सदस्य सचिव सहित सहायक निदेशक से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने इन पदों की चयन प्रक्रिया को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश उदय भान सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता दिलीप सिंह कुरका ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता भरतपुर जिले की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य पद पर आवेदन करना चाहते थे।

विभाग की ओर से अन्य जिलों में नियुक्तियों के लिए आम सूचना जारी की गई, लेकिन भरतपुर जिले की समिति के लिए कोई आम सूचना या भर्ती नोटिस जारी नहीं किया गया। याचिकाकर्ता को हाल ही में जानकारी मिली की जिला समिति के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।

ऐसे में याचिकाकर्ता ने बाल संरक्षण यूनिट के समक्ष आवेदन किया तो उसका आवेदन यह कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च को निकल चुकी है। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि भर्ती के लिए आम सूचना जारी करना जरूरी है, ताकि आमजन को इसकी सूचना मिले और इच्छुक व्यक्ति इसमें आवेदन कर सके। याचिका में गुहार की गई की आवेदन लेने की अंतिम तिथि बढाई जाए और उसकी आम सूचना जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार किए जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है।

कांग्रेस ने नीरज डांगी को पुनः बनाया राज्यसभा उम्मीदवार

जयपुर। कांग्रेस ने राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के लिए नीरज डांगी को मैदान में उतारा है। बता दें नीरज डांगी वर्तमान में कांग्रेस की ओर से राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद है और उनका कार्यकाल जून 2026 में खत्म होने वाला है। अब एक बार फिर उन्हें ही उम्मीदवार बनाया गया है। नीरज डांगी वरिष्ठ कांग्रेस नेता है, वह वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव पद पर भी कार्यरत है। डांगी पिछले 30 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और पार्टी में विभिन्न पदों पर भूमिका निभाई है। वे साल 2020 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। नीरज डांगी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी। लगातार सक्रियता के चलते साल 2002 में वे राजस्थान यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष (वाइस प्रेसिडेंट) बने। नीरज डांगी को कांग्रेस ने उन्हें साल 2003 के विधानसभा चुनाव में देसूरी सीट से टिकट दिया, लेकिन वे चुनाव हार गए। इसके बाद साल 2008 में पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए रेवदर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, मगर वे 13वीं विधानसभा में भी नहीं पहुंच सके। चुनावी हार के बावजूद पार्टी ने उनकी निष्ठा को देखते हुए 2009 में उन्हें यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके बाद 2014 में वे राजस्थान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए गए।

जयपुर में 302 सिलेंडर और दो पिकअप जब्त

जयपुर । घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी,अवैध भंडारण और रिफिलिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बडी कार्रवाई करते हुए 302 गैस सिलेंडर और दो पिकअप वाहन जब्त किए हैं। राज्य सरकार और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई जिला कलक्टर संदेश नायक के निर्देशन में की गई।

- **अवैध गैस कारोबार पर जिला प्रशासन का शिकंजा**

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि कार्रवाई के लिए दो विशेष सतर्कता दलों का गठन किया गया था। सतर्कता दल 'ए' में प्रवर्तन अधिकारी मुनेश कुमार मीणा और पूजा शर्मा तथा सतर्कता दल 'बी' में प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार और प्रवर्तन निरीक्षक सुनीता चौधरी को शामिल किया गया।सतर्कता दल 'ए' ने सांगानेर क्षेत्र के गोवर्धन नगर और हनुमान सिटी में दबिश देकर अवैध गैस भंडारण और क्रय-विक्रय का खुलासा किया। यहां से 247 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा दो पिकअप वाहन जब्त किए गए। वहीं सतर्कता दल 'बी' ने 310 फीट रोड स्थित शिक्षा सागर कॉलोनी में कार्रवाई कर 55 गैस सिलेंडर जब्त किए। दोनों स्थानों पर की गई कार्रवाई में कुल 302 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर तथा दो पिकअप वाहन (आरजे-14-जीआर-7835 और आरजे-14-जीएच-5920) जब्त किए गए। मामले में संलिप्त दो व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।

तीन दिन में 77806 किसानों से सीधा संवाद

जयपुर । कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने गुरुवार को पंत कृषि भवन में खेत बचाओ अभियान (1 से 30 जून) और खरीफ-2026 उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि अभियान के प्रथम तीन दिनों में प्रदेशभर में 2382 कृषि गतिविधियां आयोजित कर 77806 किसानों से सीधा संवाद स्थापित किया है। इनमें 294 कृषक गोष्ठियां में 13273 किसान लाभान्वित हुए।

'माइनिंग और पेट्रोलियम सेक्टर में 33 हजार करोड़ रु. के निवेश प्रस्तावों पर कार्य प्रगतिरत'

प्रदेश में अब तक 15 हजार करोड़ रु. का निवेश हो चुका : एसीएस माइंस अपर्णा अरोरा

जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम अपर्णा अरोरा ने बताया है कि राइजिंग राजस्थान के दौरान पेट्रोलियम एवं माइनिंग सेक्टर के निवेश समझौतों में 33 हजार करोड़ रु. के निवेश प्रस्तावों पर काम प्रगति पर होने के साथ ही 15 हजार करोड़ रु. का निवेश भी हो चुका है। इनमें से 6500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव लगभग पूर्णता की और हैं। अरोरा गुरुवार को सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के दौरान माइनिंग सेक्टर के निवेश प्रस्तावों की प्रगति समीक्षा कर रही थी।

उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान प्रदेश में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, डीपीएनजी-सीएनजी आधारभूत संरचना विकास, सीमेंट प्लांट, कॉपर व माइनर-मेजर मिनरलों से संबंधित निवेश प्रस्तावों पर एमओयू संपन्न हुए थे। उन्होंने बताया कि करीब 2230 करोड़ रु. के निवेश से अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट का कार्य पूरा होकर शुरु हो गया है। इसी तरह से हिन्दुस्तान कॉपर खेतड़ी में प्लांट क्षमता विस्तार पर 1000 करोड़ का निवेश कार्य पूरा होने को है। इण्डियन ऑयल द्वारा 3600 करोड़ रु. की लागत से मूंदड़ा से कच्चे तेल की पाइप लाइन बिछाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इसी तरह से माइनिंग सेक्टर में 100 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर भी काम पूरा हो चुका है। नोडल अधिकारी अधीक्षण भूवैज्ञानिक संजय सक्सैना ने विस्तार से प्रगति से अवगत कराया।

एमओयू प्रगति समीक्षा बैठक में विशिष्ट सचिव माइंस नम्रता वृष्णि, निदेशक पेट्रोलियम अवधेश सिंह, अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत, विशेषाधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा ने हिस्सा लिया।

इस वर्ष 20 अरब रु. खर्च करके स्कूलों के नए भवन और क्लास रूम बनेंगे, मरम्मत भी होगी

स्कूलों के सर्वे और री-सर्वे से मिले फीडबैक के आधार पर सुधार कार्य कर रही राज्य सरकार

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश की सरकारी स्कूलों में नए भवन और क्लास रूम बनाने तथा पुराने जर्जर स्कूलों की मरम्मत पर भजनलाल सरकार इस वित्तीय वर्ष में 20 अरब रुपए खर्च करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के तमाम सरकारी विद्यालयों के भवनों का सुरक्षा की दृष्टि से सर्वे और री-सर्वे करवाया है। इस रिपोर्ट के आधार पर नए भवन निर्माण और मरम्मत कार्य की 5 साल की कार्ययोजना बनाई है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 20 अरब रूपये के बजट से नए भवन निर्माण, अतिरिक्त सुविधाओं के विकास व मरम्मत कार्य होंगे।

गुरूवार को मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर इस प्रोजेक्ट की समीक्षा की। उन्होंने स्कूलों में निर्माण व मरम्मत कार्य में नवीनतम तकनीक, उच्चतम गुणवत्ता और समय सीमा की पालना करने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने बताया कि इस वित्त वर्ष में 500 से ज्यादा राजकीय विद्यालयों के नए भवनों का निर्माण होना है। सर्वे में कुछ ऐसे विद्यालय भवन मिले, जहां कोई कमरा विशेष ही खराब हालत में है और शेष बिल्डिंग पूरे मानकों पर खरी उतरी है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्यालयों में नामांकन बढ़ने या अतिरिक्त विषय शुरू होने के कारण अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण की जरूरत है। प्रत्येक कक्षा कक्ष निर्माण के लिए 10 लाख रूपये बजट का आंकलन किया है। विद्यालयों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था के साथ शौचालय सुविधा भी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।

सर्वे में सामने आया कि कुछ विद्यालयों के भवन 50 साल से भी अधिक पुराने हैं, ज्यादातर विद्यालय भवन निर्माण के समय प्लिंथ मानक का ध्यान नहीं रखा गया और ड्रेनेज सिस्टम सुचारू न होने से सीपेज, सीलन की समस्या आ गई है।

एसीएस राजेश यादव ने बताया कि नए भवन निर्माण में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की गाइडलाइन, बीआईएस के मानक और विशेष योग्यजन अधिनियम, 2016 के बिन्दुओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जा रही है। करीब 1 करोड़ रूपये से अधिक के निर्माण कार्य में ऑन साइट क्वालिटी कंट्रोल लैब, 30 लाख रूपये से अधिक के कार्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग और नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड द्वारा चिन्हित एजेंसी द्वारा स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण करवाया जाना सुनिश्चित किया है। बिजली बचत और बच्चों के स्वास्थ्य विशेषकर आई साइट के लिए पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था की गई है। स्ट्रक्चर डिजाइन को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा परीक्षण करने के बाद की स्वीकृति दी जा रही है। भवन की सुरक्षा और उत्तरजीविता सुनिश्चित करने के लिए आरसीसी फ्रेम डाला जा रहा है। दीवार और छत को वाटरप्रूफ बनाया जा रहा है, जिससे सीपेज और सीलन न हो। उपयुक्त ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था के बाद ही निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि विद्यालयों भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट मिलने से अधिक महत्वपूर्ण है, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, सिविल सोसायटी, भामाशाह और इंडस्ट्री का विद्यालयों की ज्यादा से ज्यादा निगरानी और उनसे जुड़ाव। उन्होंने सांसद-विधायकों से भी आग्रह किया है कि अपने स्थानीय फंड से यह कार्य करवाएं, इससे निगरानी की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को अपने फंड और विभिन्न योजनाओं से ये कार्य सीधे या कंवर्जेंस के माध्यम से करवाने के लिए बातचीत की गई है। मगरा, डांग जैसी क्षेत्रीय विकास योजनाओं के फंड से भी ये कार्य करवाने का प्रस्ताव है। साथ ही डीएमएफटी और सीएसआर से भी फंड जुटाने का लक्ष्य है।

बैठक में समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना अधिकारी डॉ. रश्मि शर्मा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट वीसी के माध्यम से बीकानेर से जुड़े।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरूवार को सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर स्कूलों के मरम्मत कार्य और नए निर्माण की समीक्षा की।

6 जून को राजस्थान आएंगे अजेय कुमार

जयपुर । भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त राजस्थान संगठन महामंत्री अजेय कुमार 6 जून को पहली बार राजस्थान प्रवास पर आएंगे। उनके दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अजेय कुमार के आगमन को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्हें राजस्थान भाजपा के संगठन महामंत्री का दायित्व सौंपा गया है।

सूत्रों के अनुसार, अजेय कुमार जयपुर में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और संगठन से जुडे प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बैठक में संगठन विस्तार, आगामी कार्यक्रमों, बूथ सशक्तिकरण अभियान तथा कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय को लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न जिलों में चल रहे संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली इस बैठक में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीति पर भी मंथन होने की संभावना है। विशेष रूप से राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों और संभावित रणनीति पर चर्चा होने की जानकारी सामने आ रही है। अजेय कुमार के दौरे को प्रदेश भाजपा के लिए नई ऊर्जा और संगठनात्मक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में भी उनके प्रथम राजस्थान प्रवास को लेकर उत्साह का माहौल है।

वंदे गंगा अभियान में जयपुर जिला प्रदेश में अव्वल

40 हजार कार्यक्रमों में 27 लाख लोगों ने भागीदारी कर रचा इतिहास

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जयपुर जिले में गत 25 मई से आयोजित हो रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान-2026 ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जिला कलक्टर संदेश नायक ने गुरूवार को मीडिया संगोष्ठी में बताया कि गंगा दशमी के पावन पर्व से शुरू होकर 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक चलने वाले इस 12 दिवसीय महाअभियान के तहत जयपुर जिले ने पूरे प्रदेश में सर्वाधिक सक्रियता दिखाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।

अभियान के दौरान जिले की ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में कुल 40 हजार से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 27 लाख से अधिक नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर जल संरक्षण को एक जन-आंदोलन का रूप दिया है। अभियान की महत्ता को रेखांकित करते हुए इसका जिला स्तरीय शुभारंभ 25 मई को पवित्र गलता तीर्थ पर हुआ था। गंगा दशमी के शुभ अवसर पर गलताजी में भव्य गंगा आरती, कलश पूजन और महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर अतिथियों और आमजन ने गलता तीर्थ के प्राचीन जल कुंड के जीर्णोद्धार और सफाई के लिए ऐतिहासिक श्रमदान किया। इसी तर्ज पर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन कर इस अभियान को गति दी गई।

मानसून से पूर्व 20 लाख गड्ढे खोदे गए हैं, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में 26 करोड़ के नए कार्य स्वीकृत हुए है। इस प्रोजेक्ट में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 5 जून को जल गौरव सम्मान से नवाजा जाएगा।

- **मानसून से पूर्व खोदे गए 20 लाख गड्ढे, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में 26 करोड़ के नए कार्य स्वीकृत**
- **उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज मिलेगा जल गौरव सम्मान**